



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 1982/फाल्गुन 26, 1903

No. 84] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 1982/PHALGUNA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 मार्च, 1982

सा० का० वि० 254 (अ)—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्न-
लिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशन की जा रही है:

यस: मुझे, भारत के राष्ट्रपति, नालम संजीव रेड्ड को केरल के
राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और मुझे प्राप्त इस रिपोर्ट
और अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें कि केरल राज्य का शासन भारत
के संविधान जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है के उपबंधों
के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा
उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करने
हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं:—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के
राज्यपाल में निहित या एतद्द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों, भारत
के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूँ;

(ख) धारित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियों
संसद के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध करता हूँ जो
इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझे आवश्यक
या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात्:—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के आधार पर
अपने हाथ में लिए गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग
करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस
समय तक जिस तक मैं ठीक समझूँ उक्त राज्य के
राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा;

(ii) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों
के प्रवर्तन को एतद्द्वारा नियमित किया जाता है, अर्थात्:—

अनुच्छेद 3 के परस्ता का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति
द्वारा राज्य के विधान मंडल को निदेश करने से है;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध
भारत के नियंत्रक-सहायिका-परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत
की गई रिपोर्ट के राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है;

अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध
राज्य सरकार के कार्यों का सक्तियों के बीच आवंटन से है;

अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना
भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प के
पारित किए जाने से है;

अनुच्छेद 174 का खंड (1) और खंड (2) का उपखंड (क);
अनुच्छेद 175 से 178 तक जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं,
अनुच्छेद 179 का खंड (ख) और (ग) और उस अनुच्छेद का
प्रथम परन्तुक और अनुच्छेद 180 और 181;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के
उपाध्यक्ष के संबलनों और मतों से है; अनुच्छेद 188, 189,
193, 194, 195 तथा 196; अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद
199 का खंड (3) और खंड (4);

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध
विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबलनों और मतों से है;
अनुच्छेद 208 से 211 तक जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं;
अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का
परन्तुक; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध शपथ
सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है;

(iii) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ
उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया
जाएगा और उसमें राज्य के विधान मंडल या विधान
सभा के प्रति किसी निदेश का, जहां तक उनका संबंध
उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ जब तक
कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों, संसद के प्रति
निदेश लगाया जाएगा, और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में
राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के
प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या
उसके सदस्यों के प्रति निदेश लगाया जाएगा;

परन्तु इसमें कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर
अनुच्छेद 159 तक जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं,
अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के
पैरा 1 से 4 तक जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं के उपबंधों
पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को इस खंड के
उपखंड (1) के अधीन उस सीमा तक जहाँ तक वह ठीक
समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से
निवारित करेगी;

(iv) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या एतद्वारा
बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश
का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उनके प्रारम्भ इस
उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या
संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड
(क) और केरल राज्य में यथा प्रवृत्त केरल निवर्धित
तथा साधारण खंड अधिनियम 1125 (1125 का अधि-
नियम 7) में निविष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के
विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए
गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है, और
साधारण खंड अधिनियम 1897 (1897 के दसवें)
का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है;
ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रस्तावी
होंगा मानो यह उस राज्य विधान मंडल का अधिनियम
हो।

नई दिल्ली,
ता० 17 मार्च, 1982

नीलम संजीव रेड्डी
राष्ट्रपति

नई दिल्ली,
ता० 17 मार्च, 1982

[सं० 5/11013/1/82-सी०एस०आर०]
दिल्ली की नाथ अनुवैसी, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1982

G.S.R. (254) (E)—The following proclamation by the President is published for general information:—

Whereas, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, have received a report from the Governor of the State of Kerala and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Kerala cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the reports submitted to the Governor by the Comptroller & Auditor-General of India; articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1), and sub-clause (a) of clause (2), of article 174;

articles 175 to 178 (both inclusive);

clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196; article 198 and clauses (3) and (4) of article 199;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive); the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the House thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively;

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive) article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Interpretation and General Clauses Act, 1125 (Act VII of 1125) as in force in the State of Kerala, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi;
The 17th March, 1982

NEELAM SANJIVA REDDY,
President.

[V. 11013/1/82-CSR]

New Delhi;
The 17th March, 1982

T. N. CHATURVEDI
Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1982

सा० का० नि० 255 (अ)—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज मार्च, 1982 के सप्तरहवें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खंड (4) के उप-खंड (1) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्वारा निदेश देता हूँ कि केरल राज्य सरकार के सभी कृत्य और मौखिक के अधीन या उस राज्य में प्रयुक्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या प्रयोजन्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के आधारे पर आने ह्राथ में ले लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण के अध्याधीन रहने हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोजन्य होंगी।

नई दिल्ली,
17 मार्च, 1982

नीलम संजिव रेड्डी,
राष्ट्रपति

नई दिल्ली,
ता० 17 मार्च, 1982

[सं० V/11013/1/82 सी० एम० आर]
त्रिनीको नाथ चतुर्वेदी,
सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th March, 1982

G.S.R. 255(E)—The following Order by the President is published or general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 17th March, 1982, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Kerala and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi;
The 17th March, 1982.

NEELAM SANJIVA REDDY,
President.

[No. V. 11013/1/82-CSR]

New Delhi;
The 17th March, 1982.

T.N. CHATURVEDI,
Secy.

